बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा नेपाल को बिजली सप्लाई करने के लिए समझौता

698. **श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने नेपाल सरकार से एक दीर्घकालीन समझौता किया है जिससे नेपाल में बिजली की आपूर्ति और उत्पादन किया जाये ;

(ख) क्या उपरोक्त बोर्ड ने इस प्रयोजन के लिए केन्द्र से कोई धनराशि मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी, और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने नेपाल में बिजली के उत्पादन और सप्लाई के लिए नेपाल सरकार से कोई दीर्घकालीन समझौता नहीं किया है। बहरहाल, एक व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत बिहार राज्य बिजली बोर्ड और नेपाल सीमावर्ती शहरों को सप्लाई के लिए बिजली का आदान में आदान-प्रदान करते है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Decline in Saving and Investment in Private Sector

699. SHRI ARJUN SETHI: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there has been declining of employment in the organised private sector since 1973, simultaneously with the decline in the level of saving and investment;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) actions taken by Government to meet the challenges therefrom?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): (a) to (c). A statement showing employment in the organised sector since March, 1973 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-10454/76] It would be seen that total employment covering both organised private and public sectors increased by 2.4 per cent during 1973-74 and 1.9 per cent during 1974-75 over the previous year. Employment in the private sector however registered a decline of 0.8 per cent in 1973-74 and an increase of 0.2 per cent in 1974-75 over the previous year. Decline in employment in the private sector during 1973-74 is attributed largely to transfer of coking coal mines from private to public sector as well as the effects of power shortage, energy crisis and other factors that had affected industrial growth in that year. Apart from measures to boost industrial growth, which is likely to have a positive impact on the employment situation, the Government has also recently taken steps to amend the Industrial Disputes Act in order to check resort to retrenchment, lay-offs and lock-outs in industry.

खादी के कपड़ों का मूल्य

700. **श्री नाथूराम मिर्हरवार** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में खादी के वस्त्रों के मूल्यों में शत प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग में लगे कामगरों की मजदूरी में कितनी वृद्धि हुई ?